अब कॉलेजों व यूनिवर्सिटीयों के कैम्पस खुल गये हैं। पढ़ाई–लिखाई को 2 वर्षों में हुई क्षति की भरपाई का सवाल सामने खड़ा है।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

कोविड के कारण दो वर्षों तक बन्द रहने के बाद यूनिवर्सिटीयों और कालेजों के कैम्पसों में फिर से चहल–पहल होने लगी है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और बीएचयू जैसे नामीगरामी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने द्वार सामान्य पठन–पाठन के लिये खोल दिये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भेजे गये निर्देशों के अनुसार अब कोविड से सम्बन्धित सभी नियंत्रणों को हटा दिया जाना चाहिये।

मीडिया रिपोर्टो के अनुसार अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तामिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्यों में कैम्पसों को खोल दिया गया है। कैम्पसों को खोलने के फैसले से विद्यार्थी वर्ग जहां एक ओर राहत महसूस कर रहा है, वही उनमें से बड़ा समुदाय कुछ कठिनाईयों का भी सामना कर रहा है।

हमारे देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को होस्टल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। लाखों विद्यार्थियों को प्राईवेट होस्टलों या पी.जी. का सहारा लेना पड़ता है। जो विद्यार्थी होस्टलों में नहीं रहते उन्हें अपने घरों से बसों या रेल यात्रा करके रोजाना पढ़ने आना पड़ता हैं। कैम्पसों के खोलने के फैसले से पहले होस्टलों को तैयार रखने की अपेक्षित तैयारियां शायद नहीं हो पाई हैं।

कैम्पसों को खोलने के बारे में यूजीसी ने भी पिछले हफ्ते एक आदेश जारी करके कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को कैम्पस खोलने, कक्षाओं और परीक्षाओं को

ऑनलाइन, ब्लेन्डेड अथवा पारम्परिक रूप में करने की अनुमति दे दी गई है बशर्ते कि वे केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्गत कोविड निदेर्शो को पालन करते रहें। यूजीसी ने 18 पृष्ठों की एक निर्देशिका भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि कैम्पसों को खोलने से पहले राज्य सरकारों को यह फैसला लेना होगा कि कैम्पस जिस शहर, कस्बे या स्थान पर हैं, वे कोविड से प्रभावित नहीं हैं।

कैम्पसों को खोलने के फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिये, किन्तु देश के 1000 विश्वविद्यालयों और 45000 कालेजों में पढ़ने वाले 3.84 करोड़ विद्यार्थियों को अब बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। कैम्पसों में दो सालो से चल रही तालाबंदी उच्च शिक्षा के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना ही कही जायेगी। यह सवाल रह–रह कर उठेगा कि करोड़ों विद्यार्थियों की पढ़ाई–लिखाई में दो सालों तक चली कैम्पस तालाबंदी से हुई अभूतपूर्व क्षति की भरपाई कैसे की जायेगी? क्या उच्च शिक्षा को इुई इस ऐतिहासिक क्षति को सामान्य ढंग से पूरा किया जा सकेगा या फिर इस के लिये विशेष उपाय करने होंगे?

दो सालो से चली आ रही कैम्पस बंदी से सिर्फ भारत के 3.84 करोड़ युवा विद्यार्थियों और 28 करोड़ स्कूली छात्रों को ही नुकसान नहीं हुआ है। पढ़ाई लिखाई की यह क्षति एक विश्वस्तरीय समस्या बन के उभर रही है। वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को और यूनिसेफ ने विश्व में शिक्षा के मौजूदा संकट और उससे निपटने के रास्ते के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित कर के जो आधिकारिक आंकड़े दिये है, वे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के विद्यार्थियों को कोविड के कारण पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, उससे उन की भविष्य की कमाई में 17 ट्रिलियन डालर का नुकसान होगा। यह नुकसान दुनिया के सालाना जीडीपी का 14 प्रतिशत और भारत के वर्तमान जीडीपी के छः गुने के बराबर है।

वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को और यूनीसेफ की उपरोक्त रिपोर्ट में दुनिया के देशों को दो सालों की कैम्पस बन्दी से हुए भारी नुकसान ने निपटने के लिये भी अनेक सुझाव

दिये गये हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सभी देशों की सरकारों को **'लर्निंग रिकवरी प्लान'** बना कर यह सुनिश्चित करना चाहियें कि कोविड काल के दौर से गुजर रही विद्यार्थियों की पीढ़ी को पिछली पीढ़ियों की तरह योग्य, सक्षम और रोजगार परक बनाया जा सके। इस के लिये मौजूदा पाठ्यक्रम में बदलाव करने होंगे, कक्षाएं अधिक समय तक चलानी होंगी और पढ़ाने के तौर तरीकों को अधिक प्रभावी बनाना होगा।

कालेजों और यूनिवर्सिटियों के कैम्पसों को खोला जाना एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्या हमने राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई 'लर्निंग रिकवरी प्लान' बनाये हैं? क्या हम पुराने पाठ्यक्रमों और पढ़ाने के तौर तरीकों से दो सालों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई कर पायेंगे? क्या हमारे क्लास रूम, होस्टल, लायब्रेरी और लेबोरेटरी विद्यार्थियों को हुए नुकसान की जल्दी से भरपाई करने के लिये तैयार कर लिये गये हैं? क्या हम 12 लाख यूनिवर्सिटी शिक्षकों को ऐसे प्रशिक्षण दे पायेंगे कि वे पिछले 170 वर्षों में उच्च शिक्षा को हुई अभूतपूर्व क्षति की समस्या से निपट सकें। अब तक हम ऑनलाइन कक्षाएं लगा कर यह सोचते रहे कि हमने युवा विद्यार्थियों को एक विकल्प दे दिया है।

पिछले दो वर्षों के कोविड–काल में केन्द्र व राज्य सरकारें महामारी से जनित स्वास्थ्य संकट से निपटने में ही लगी रहीं। लगता है शिक्षा हमारे चिंतन में अब तक तात्कालिक प्राथमिकता नहीं है। हमारी सरकारें कारखानों, बाजारों, रैस्टोरेंटो, होटलों, जिम, सिनेमाघरों और मॉल्स को फिर से खोलने के लिये जितनी चिंतित रही, उतनी चिंता स्कूलों और कालेजों को खोलने के लिये नहीं दिखाई दी। शायद यह मान लिया गया कि विद्यार्थी ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और काम चल रहा है।

21वीं सदी के तीसरे दशक में डिजीटलाइजेशन, टैक्नोलॉजी और ऑनलाइन शिक्षा को अल्लाद्दीन का चिराग समझा जाने लगा है। कोविड काल में हमने भी मान

किया कि स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल और कालेजों के विद्यार्थी घर पर मोबाइल, लैपटॉप और कम्पयूटरों के सामने बैठकर पढ़–लिख सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि देश की बहुसंख्यक जनता के पास डिजिटल युग में घुसने के लिये जरूरी संसाधन नहीं हैं। क्या शिक्षा किसी स्क्रीन के सामने घण्टों बैठकर, मोबाइल पर चल रहे ऑडियो या व्हाट्सएप पर आने वाले कोर्स मैटेरियल से ही प्राप्त की जा सकती है? स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बारे में इस से ज्यादा गलत कोई धारणा नहीं हो सकती कि ऑनलाइन शिक्षा सभी समस्याओं का हल है।

कैम्पसों के खुलने के बाद हमें युवा विद्यार्थियों की मौजूदा हालत पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये। ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाने का मुख्य माध्यम नहीं होना चाहिये। असली पढ़ाई शिक्षकों व विद्यार्थियों के बीच कक्षाओं में चलने वाले संवाद पर निर्भर होनी चाहिये। ऑनलाइन माध्यम इस में सहायक की भूमिका निभा सकता है। हमें गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को लैपटॉप, पीसी या टेबलेट देकर डिजीटल असमानता से भी बचाना होगा। केन्द्र व राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत खर्च कर रही हैं। क्या शिक्षा पर होने वाले मौजूदा खर्च को सकल मौजूदा राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है?

उच्च शिक्षा में कोविड से पैदा हुए पढ़ाई के अभूतपूर्व घाटे को दूर करने के लिये यूनेस्को को कहना है कि कैम्पस खुलने पर पढ़ाई–लिखाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिये 'लक्ष्य केन्द्रित' टेकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। इस में शिक्षक विद्यार्थियों को पुराने तौर–तरीकों से पढ़ाने की बजाय उनके मौजूदा हालात को देखकर अपने शिक्षण को उस के साथ समायोजित करता है। एक ही कक्षा में अलग–अलग विद्यार्थियों को स्तर भिन्न हो सकता है। हम विद्यार्थियों से यह उम्मीद न करें कि वे शिक्षक के स्तर से तालमेल बैठाये। 'लक्ष्य केन्द्रित' पढ़ाई के लिये 'लर्निंग लॉस' से सम्बन्धित आंकड़ो की भी जरूरत होगी और हमें शिक्षकों को पढ़ाने के लिये अधिक और बेहतर संसाधन भी देने होंगे।